

प्रेषक,

एन०एस०नपलच्याल,
प्रमुख राक्षिव,
उत्तराखण्ड शासन।

रोधार्गे,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: ०७ मई, २००८

विषय:- श्री बलराम त्यागी पुत्र श्री तोजराम त्यागी, निवासी ३०६, ग्राम बुराडी, दिल्ली को जनपद उधमसिंहनगर की तहसील किच्छा के ग्राम भमरौला में कुल ०.९५०० है० भूमि होटल बनाने हेतु कय करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- २१२/सात-स०भू०अ०/२००७ दिनांक २३ अगस्त, २००७ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री बलराम त्यागी पुत्र श्री तोजराम त्यागी, निवासी ३०६, ग्राम बुराडी, दिल्ली को होटल बनाने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, २००१) (संशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक १५-१-२००४ की धारा-१५४(४)(३)(क)(ii) के अन्तर्गत तहसील किच्छा के ग्राम भमरौला के खाता सं०-११०, खसरा न० २७४ मध्ये रकबा ०.९५०० है० भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

१- क्रेता धारा-१२९-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

२- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-१२९ के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

३- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिराकी गणना भूमि के विकय विलेख के मंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उससे बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिराकी राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिराके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह

ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे रवीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके मूखामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा ऐसे प्रत्येक प्रकरण को आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी स्वतः स्पष्ट आदेश से निस्तारित कर ही भूमि अन्तरण के आदेश करेंगे।

5- चूंकि होटल उद्योग प्राथमिकता क्षेत्र का उद्योग है अतः इस योजना हेतु विशेष पैकेज का लाभ निगमानुसार अनुमन्य होगा।

6- किसी दशा में क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।

7- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

8- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके मूखामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

9- यह रवीकृति 180 दिनों के लिये वैध होगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 02 वर्ष के भीतर योजना का निर्माण कार्य पूरा करना होगा।

10- प्रस्तावित होटल/रिजोर्ट में प्रदेश के उपायी निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11- नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकताएँ/ अनापत्तियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

12- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे

शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
- 4- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 6- श्री बलराम त्यागी पुत्र श्री तजोराम त्यागी निवासी 306, ग्राम बुराडी, दिल्ली।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)

अनुसचिव।